

‘मेक इन इण्डिया’ का आधार कौशल का विकास एवं शैक्षिक मोर्चाबन्दी – एक अध्ययन

Dr. Munesh kumar Sharma
H.O.D (Department of Education)

Mrs. Monika
Assistan Professor

SHRI MADHAV COLLEGE OF EDUCATION AND TECHNOLOGY
KESHAV NAGAR, MODINAGAR ROAD, HAPUR, UTTAR PRADESH

सारांश

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग निश्चय ही पाठशालाएँ भी हैं और उनके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन भी आवश्यक है। शिक्षा में परिवर्तन की बात कही तो सर्वत्र जाती है, लेकिन स्कूली शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की कोई स्पष्ट स्थिति विनिर्मित नहीं हो सकी है। आज प्रशिक्षण व कौशल के अभाव में सारी विपन्नताएँ उठ खड़ी हुई हैं।

स्वतन्त्रता देशवासियों की एक अत्यन्त शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकता थी और इसके लिए वे सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। आज उसी बलिदान स्तर की आवश्यकता है तथा ‘मेक इन इण्डिया’ को आधार बनाकर कौशल का विकास, शैक्षणिक पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना है और उसके लिए शिक्षा विभाग तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को देश के निर्माण के कार्य लिए आगे आना है। प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्ता पर आज के विचारक एवं बुद्धिजीवी एक मत है। यहाँ वह सॉचा है, जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व ढाला और वातावरण बदला जा सकता है। अनेकों मतभदों के बावजूद अधिकांश चिन्तक दो घटकों—कुशल प्रशिक्षक एवं अनुकूल वातावरण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्रधानता मानते हैं।

कुँजी शब्द:- कौशल ,शैक्षिक मोर्चाबन्दी, रोजगार ।

प्रस्तावना

इन दिनों शिक्षा प्रणाली की उस समग्रता में बहुत कुछ कमी रह जाती हैं, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करके किसी प्रकार पास होना ही एक मात्र लक्ष्य रहता है। जिसका वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में भी अत्यधिक महत्व दृष्टिगोचर होता है। समय के बदलते हुए क्रम को देखते हुए शिक्षा के उद्देश्य और स्वरूप में असाधारण परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों का क्षेत्र सीमित मानकर शिक्षा से जुड़ने वाले हर छात्र और अभिभावक को यह सोचना होगा कि नौकरी के लिए शिक्षा वाले दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से जिसे जितना अधिक पढ़ने का अवसर मिल सके उत्तम है ,परन्तु उसे आजीविका के साथ जोड़ना हो तो यह समझकर चलना चाहिए कि हर शिक्षित को इन दिनों नौकरी मिलना असम्भव है। सामान्य शिक्षा के उपरान्त जब अर्थोपार्जन पर भी ध्यान देना पड़े तो पूर्व से ही सोच लेना चाहिए कि नौकरी न मिलने की दशा में क्या करना होगा?।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लोगों के लिए जो अतिरिक्त मार्ग खुला रह जाता है। वह कुटीर उद्योगों व क्षेत्रीय व्यवसायों का ही है। कुटीर उद्योगों का क्षेत्र अभी भी बचा हुआ है ,कुटीर उद्योगों को बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से अभी बहुत विस्तार दिया जा सकता है। जापान जैसे देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति कुटीर उद्योगों के स्टोर से ही विकसित हुई है। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं में से अधिकांश ऐसी है ,जो

समीपवर्ती क्षेत्र में बनने पर किसी फैक्टरी के चमकदार माल की तुलना में सस्ती भी हो सकती है तथा टिकाऊ भी। यदि कच्चा माल अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो और क्षेत्रीय निर्माण को प्राथमिकता देने की लोक रूचि हो तो निश्चित ही अभी भी कुटीर उद्योग बड़े-बड़े मिलों के निर्माण की प्रतिस्पर्धा में टिकी रह सकती है। गांधी जी ने खादी को प्राथमिकता देते हुए सर्वसाधारण का ध्यान कुटीर उद्योगों की ओर आकर्षित किया था तथा स्वदेशी भावना को ग्राम विकास की रीढ़ बनाया था। कुटीर उद्योगों को यदि सुनियोजित ढंग से अपनाया, शिक्षा तन्त्र के साथ उसका समन्वय किया जाये तो शिक्षितों की बेरोजगारी वाली समस्या का समाधान पूर्णरूप से निकल सकता है।

किसी भी संतुलित शैक्षिक व्यवस्था में इस प्रकार के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सोच, अनुभव, संवेदनाएं प्रत्यक्षीकरण को समान रूप से विकसित किया जा सके। वस्तुतः तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक रूपान्तरण के कारण आज संयुक्त परिवारों में विघटन हो रहा है तथा असन्तोष बढ़ रहा है। आज हम भौतिक और आर्थिक क्षेत्र की उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं और उसमें सफलता की आशा भी दिख रही है, लेकिन परिवारिक व सामाजिक विघटन तथा आर्थिक-सामाजिक असमसन्नता को रोकने के लिए शिक्षण क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इस सुधार के बिना राष्ट्र की विशेष प्रगति में सन्देह ही रहेगा। प्रस्तुत शोधकार्य उसी समस्या समाधान का एक प्रयास है।

अध्ययन के उद्देश्य: (Objective of the study):

1. भारत में कौशल विकास के मौजूद स्तर का अध्ययन करना।
2. कौशल विकास की आवश्यकता का विश्लेषण करना।
3. कौशल विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त तरीकों का पता लगाना।

शोध विधि: (Research methodology):

इस शोध के लिए अनुसंधान डिजाइन में वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन को चयनित किया गया है। सही क्रम में डेटा एकत्र करने के लिए डेटा संग्रह की द्वितीय डेटा संग्रह विधि का प्रयोग किया गया है। डेटा , पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित लेख ,शोध-पत्र व वेबसाइटों से एकत्रित किये गये हैं।

भारत में कौशल शिक्षा का वर्तमान स्तर : (Present status of skills in India):

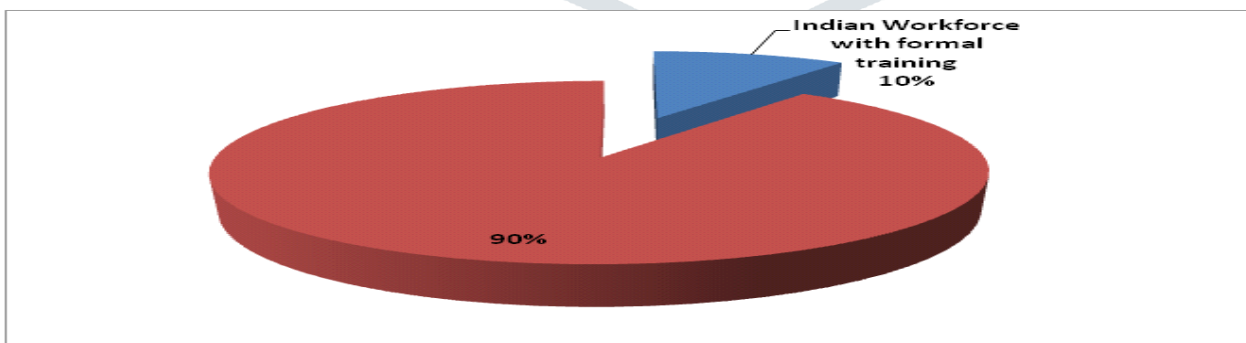


Chart 1 (Source: Planning Commission India - 11th five year plan)

भारतीय को कौशल का केवल 10% ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण दिया है।

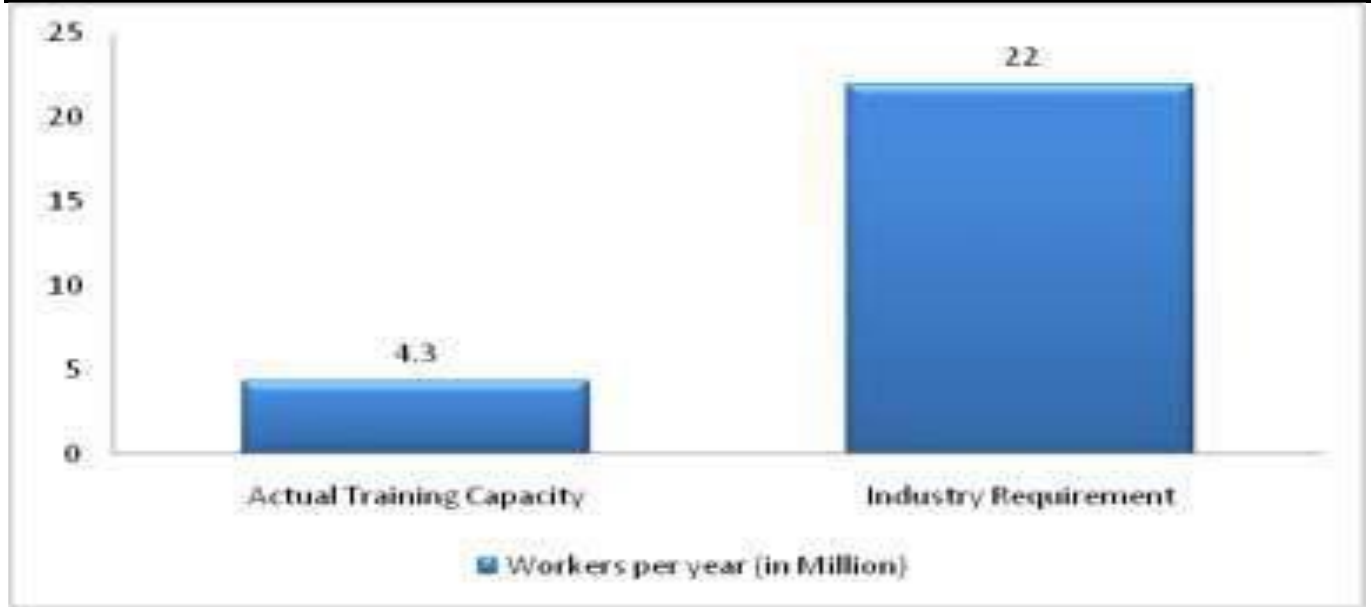


Chart 2 (Source: Planning Commission India - 11th five year plan)

भारत में वर्तमान में 4.3 करोड़ की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता है, जो 22 लाख कुशल श्रमिकों को एक साल के लिए उपयोग की आवश्यकता के 20% से कम है।

भारतीय सरकार के द्वारा कौशल विकास के लिए की गई पहल

- 1- डी.जी.ई.टी. के माध्यम से 1,500 नये आईटीआई की स्थापना।
- 2- डी.जी.ई.टी. के माध्यम से 50,000 कौशल विकास केन्द्र की स्थापना।
- 3- डी.जी.ई.टी. के माध्यम से 50,000 कौशल विकास केन्द्र की स्थापना।
- 4- कौशल विकास पर प्रधानमंत्री परिषद की स्थापना।
- 5- राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड की स्थापना।

इनके अलावा भारत सरकार के कई मंत्रालय भी कौशल विकास में लगे हैं

- 1- कपडा मंत्रालय।
- 2- ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- 3- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना।
- 4- शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की स्थापना।
- 5- एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की स्थापना।
- 6- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना।

अन्य देशों में कौशल विकास लागू करने की रूपरेखा

जर्मनी:- जर्मनी ने शिक्षा की दोहरी प्रणाली को अपनाया जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर तथा स्कूल के आधार पर पूर्णकालिक रोजगार के लिए प्रशिक्षुओं को तैयार किया जाता है। ये प्रशिक्षण दो से साढ़ें तीन साल का होता है जोकि एक ही रोजगार से सम्बन्धी होता है। प्रशिक्षुक एक सप्ताह में एक या दो दिन व्यावसायिक स्कूल में तथा तीन या चार दिन अपनी कम्पनी में बिताता है। अन्त में प्रशिक्षुक की परीक्षा होती है।

दक्षिण कोरिया :-दक्षिण कोरिया भी आज एक विकासशील अर्थव्यवस्था का स्वच्छ उदाहरण प्रस्तुत करता है। दक्षिण कोरिया ने कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के तहत रोजगार बीमा प्रणाली के रूप में एक ढांचा तैयार करके बेरोजगारों से छुटकारा पाने में सफलता पाई।

सिंगापुर:—सिंगापुर ने एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जिसके अर्न्तगत राष्ट्रीय कौशल पहचान प्रणाली (NSRS)

को अपनाया। मानकों की स्थापना, नौकरी दक्षताओं की पहचान और कौशल को प्रमाणित करके उत्पादकता – दक्षता व नवाचार बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रशिक्षित श्रमिकों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन केन्द्र स्थापित है।

भारत में कौशल शिक्षा की आवश्यकता: (Need of skill Education in India):

सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली को अपनायान का निश्चय किया। गॉंधी जी ने शिक्षा का विश्लेषण करते हुए कहा था "कि जो शिक्षा चरित्रवान न बना सके, मन इन्द्रियों को वश में न रख सके, आत्मविश्वास न बना सके, स्वावलम्बी न बना सके, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकरी का भण्डार, तार्किक विशेषता अथवा पाण्डित्य हो वह अपूर्ण है।"

हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया। शिक्षा मानव जीवन की पहली सीढ़ी है जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई भी मानव अपने राष्ट्र को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचाता है। भारत के करोड़ों देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें शीघ्रतीशीघ्र अपने आर्थिक उत्पादन बढ़ाने हैं। किन्तु उत्पादन बढ़ाने की शर्तों में यह भी शामिल है कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो तथा वे आधुनिक, आर्थिक एवं औद्योगिक संगठन और प्रक्रियाओं से परिचित हो। इन तीनों बातों के लिए ही हमें लाखों परिश्रमियों की आवश्यकता है। इन सब परिश्रमियों को ये समझना होगा कि इनके कौशल के आधार पर ही करोड़ों देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का यह कार्य सम्भव होगा। यही कारण है कि आज कौशल शिक्षा प्रसार का महत्व पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव किया जाने लगा है।

सामान्य अर्थ में स्वावलम्बन को रूपये कमाने में प्रयुक्त किया जाता है परन्तु स्वावलम्बन केवल कमाने तक ही सीमित नहीं है। इस का अर्थ अपने उपार्जन और व्यय का समन्वय स्थापित करना भी है। घर के कामों व पिता के व्यवसाय में सहयोग देना हुआ शिक्षार्थी शिक्षा पाएगा तो ये भी समन्वय स्थापित का प्रशिक्षण है। वह प्रत्यक्ष में कोई रूपये-पैसे नहीं कमाते हुए भी स्वावलम्बन को कुछ अर्थों में पूरा करता है, तथा शिक्षार्थी को धन व आवश्यकता के बारे में ज्ञान हाता है। नौकरी के लिए ही पढ़ाई एक मात्र लक्ष्य रखना ये बात जितनी जल्दी दिमाग से निकलवाने की कोशिश की जाये समाज व राष्ट्र के लिए उतना ही अच्छा होगा। वर्तमान शिक्षा एकांगी है। वास्तविक शिक्षा वह है, जिससे मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों पथ का पथिक बन सके, जिससे मनुष्य का तन सबल, मन स्वच्छ हो, मनुष्य छल-प्रपंचरहित, परोपकारी, बुद्धिमान तथा एक सुयोग्य नागरिक बने वही सच्ची शिक्षा कही जा सकती है। मानव जीवन के उत्थान में वही शिक्षा सार्थक है, जो उसके विवेक, पुरुषार्थ, सेवा कृतज्ञतादि भावनाओं को विकसित करे।

आज की स्थिति:

भारत में कुटीर उद्योगों पर आधारित जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति भी भारत में हैं जो एक प्रकार से व्यावहारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भारत में 70 प्रतिशत जनता 35 वर्ष से कम आयु-वर्ग की है, इसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में सुख एवं शांति स्थापित करने के लिए अनेक देश भारत की ओर निहार रहे हैं और संभवतः भारत से उनकी यह अपेक्षा भविष्य में पूरी हो। परन्तु आज सामान्यतया भारत में बेरोजगारों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है, यह देखकर भारतीयों तथा अन्य देशों के निवासियों को निराशा हो रही है। मनुष्य में जब तक राष्ट्रीय, धार्मिक जातीय, सामाजिक और पारवारिक मान्यताओं अथवा परम्पराओं के प्रति समान बुद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उन्नति की आशा दुराशामात्र

है। विश्व के सभी मूर्धन्य विचारकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के तीन प्रमुख लक्ष्य बताए हैं—1. स्वावलम्बन 2.व्यक्तित्व का निर्माण 3.सामाजिक सदभावना का विकास। शिक्षा की पूर्णता एवं समग्रता इन तीनों के समन्वय से बनती है। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज भारत में इन तीनों को ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।

सुझाव: (suggestions):

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक त्रुटियाँ हैं परन्तु इन सबका एक साथ परिवर्तन होना कठिन है। अतः उनमें से जो सुधार सरल व अधिक आवश्यक हो उसी की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे सुधार निम्नलिखित हैं—

1. पाठशाला में प्रवेश करते समय बालक की आयु छः वर्ष से कम न हो, क्योंकि छोटी आयु में शिक्षा का दबाव पड़ने से बालक के स्वास्थ्य मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता।
2. पाठ्यक्रम में व्यवहारिक जीवन सम्बन्धी जानकारियों को स्थान आवश्य दिया जाये, जिसमें विद्यार्थियों को स्वास्थ्य , यात्रा, शिष्टाचार ,रेल, डाक, व्यापार तथा राजकीय नियमों की आवश्यक जानकारी हो जाये।
3. सब प्रान्तों में एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम हो, जिससे एक प्रान्त के विद्यार्थियों को दूसरे प्रान्त में जाने पर दाखिला सम्बन्धी कोई अड़चन न हो।
4. छात्रों और अध्ययपकों की आदतें,वेषभूषा तथा अनुशासनप्रियता पर कड़ाई से ध्यान दिया जाये। उच्छृंखलता को शिक्षा के क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाये। सफाई, सादगी, सदाचार, शिष्टाचार और सेवा भाव को पुरस्कृत एवं प्रशिक्षित किया जाये।
5. सरकारी धन उच्च शिक्षा पर अधिक व्यय होने की अपेक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर अधिक व्यय होना चाहिए।
6. स्कूलों में औद्योगिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जो कम-से-कम प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य हो।
7. लड़कियों की शिक्षा में उनके भावी जीवन से सम्बन्ध रखने वाली जानकारियों का आवश्यक समावेश रहे।
8. सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कौशलों के विकास पर ध्यान दिया जाये।
9. बच्चे माँ-बाप साथ कार्य करके दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तथा कुशल कारीगर बन जाते हैं। अतः परम्परागत कुटीर उद्योगों को पहचान करके उन्हें पोषित करना चाहिए।
10. कर्मन्द्रियों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है, जिससे छात्र प्रतिभा सम्पन्न होता है।
11. शैक्षिक व प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों का चयन किया जाना चाहिए।

आज शिक्षा में छोटे स्तर से ही कृषि बागवानी, कताई-बुनाई, लकड़ी का काम , आदि कौशलों को सिखाना चाहिए ताकि वह अपने पाँवां पर खड़ा हो सकें। शिक्षित व्यक्ति अपने हाथ स काम करना में उसे अपना अपमान लगता है। अपना काम स्वयं करने में जहाँ गर्व की अनुभूति होनी चाहिए ,उसके स्थान पर लज्जा आती है ये सब दोष पाठ्यक्रम व शिक्षा पद्धति का ही है। अतः प्राथमिक एवं माध्यमिक से ही सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कौशलों के विकास पर ध्यान केंद्रीत किया जाये।

अध्ययन का निष्कर्ष(Conclusions of stady):

मानसिक श्रम करने तथा सिनेमा तथा फैशन परस्ती के शिकार ये शिक्षित युवक शारीरिक श्रम करना पसन्द नहीं करते और न समय बन्धन का मूल्य ही समझ पाते हैं। इन सब का एक ही कारण है कि शिक्षा के साथ स्वावलम्बन का जोड़कर नहीं रखा गया। गॉंधी के सर्वोदय कार्यक्रम इसी आधार पर बनाये और चलाये

थे। ऐलोपैथी के विरोध में उन्होंने उरुली कांचन का प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम बनाया था और दूसरी ओर फ़ैक्टरियों व मिलों से झगड़ने की अपेक्षा चरखा आन्दोलनों को गति दी। जो एक सफल क्रान्ति का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है।

नारी का कौशल विकास एक स्वतन्त्र विषय है। महिलाओं को आमतौर से गृहव्यवस्था, शिशुपोषण, परिवारिक सहयोग, अतिथि सत्कार आदि अनेकों दायित्व सँभालने पड़ते हैं। अन्नापूर्णा सच्चे अर्थों में वही है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि गरीबी में भी पोषणयुक्त आहार देकर किस प्रकार घर में सभी सदस्यों को निरोग रखा जा सकता है। नारी को सच्चे अर्थों में गृहलक्ष्मी बनाने की शिक्षा न तो स्कूलों में ही मिलती है और न अभिभावक ही अपनी अयोग्यता के कारण ऐस अभ्यास करा पाते हैं। नारी उचित कौशल विकास की शिक्षा प्राप्त करके भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अच्छा हो कि महिला-संस्कारशाला, बाल-संस्कारशाला में कौशल का विकास निजी व सरकारी क्षेत्रों द्वारा चलाया जाये। सरकार इन सब बिन्दुओं का समन्वय अपने प्रशिक्षण तन्त्र को समग्र बनाने के लिए कर सकती है, जिससे उज्ज्वल भविष्य का शानदार सुयोग बन सकता है।

भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में लघु उद्योगों व कुटीर उद्योगों का विकास बहुत आवश्यक है। अधिक खर्चीली शिक्षा जैसे डॉक्टरी, इन्जीनियरिंग आदि के साथ-साथ उसी धन में से लघु उद्योग व कुटीर उद्योग में लगाकर उसे अपने बच्चे के हाथों में दे देने से बेरोजगार रहने की आशंका न रहगी।

संदर्भ ग्रंथ (REFERENCES):

1. www.makeinindia.com
2. Planningcommission.gov.in
3. www.ndtv.com
4. www.forbesindia.com
5. Economic Times (e-paper)
6. Business Standard (e-paper)
7. Times of India (e-paper)
8. Live Mint (e-paper)
9. The Hindu Business Line (e-paper)
10. Financial Express (e-paper)
11. Vidhya awam shiksh-Pt.shri Ram Sharma.
12. Development of Edu.system in India-G.S.Varma